

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 19

प्रति सोमवार, 28 सितंबर 2026

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

9 माह बाद भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन

■ भेदभाव करने में अव्वल है नितिन पार्टी कार्यालय के बाहर भी आने लगा है नितिन नबीन के प्रति कार्यकर्ताओं का गुस्सा

**कवर
स्टोरी**
-विजया पाठक
एडिटर



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी के शीर्ष पद पर बैठे हुए लगभग 9 महीने का समय पूरा होने को आया। लेकिन 09 महीने में नितिन नबीन ने ऐसे 09 कार्य भी नहीं किये जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्हें करना चाहिए। उनके कार्यकाल में पार्टी कार्यकर्ताओं



कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का था दबदबा

अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतिहास पर नजर डालें तो उस समय में और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर सामने आता है। एक समय था जब इस पार्टी की कमान लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह,

वैकेया नायडू, अमित शाह, डॉ. जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेताओं के हाथ में थी। लेकिन इस बार पार्टी आलाकमान ने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को साधने के लिए नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठाकर जो प्रयोग किया है उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में पार्टी को झेलना पड़ सकता है। सुत्रों के अनुसार पार्टी के आलादर्जों के नेता बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई प्रभावी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसी कारण उन्होंने डमी कैडिडेट के रूप में नितिन नबीन जैसे हारे हुए व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा।

छत्तीसगढ़ में फूट डालने का किया था काम

वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने नितिन नबीन को प्रदेश प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। सुत्रों के अनुसार नबीन ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच ऐसी फूट डाली कि पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल हो गया था। जब छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को नितिन नबीन की इस दोहरापन का पता चला तो उन्होंने अपने बल पर चुनाव की तैयारियां आरंभ की और मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं नबीन ने जबरदस्ती दबाव बनाकर कुछ दिनों पहले गौतम अदाणी की कंपनी को 1200 करोड़ रुपये की खदान दिलवाई। (शेष पेज 3 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से जनजातीय परिवारों के लिए बढ़े आजीविका के अवसर जंगल की महक से बाजार की पहचान तक, जशपुर के महुआ को मिल रहा नया स्वरूप

-विजया पाठक

कभी जंगलों में सहज रूप से मिलने वाली वन उपज और पारंपरिक उपयोग तक सीमित महुआ अब प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, अनुसंधान और आधुनिक बाजार से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महुआ को नए खाद्य उत्पादों के रूप में विकसित करने और उससे जुड़े जनजातीय परिवारों तथा महिला स्वसहायता समूहों



के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में स्थानीय एवं जनजातीय उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल की झलक रायपुर के साईंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में देखने को मिली। 18 से 20 सितंबर तक आयोजित मेले में जशपुर और जय जंगल के स्टॉल पर जशपुर के महुआ से तैयार विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए। (शेष पेज 2 पर)



2019 में कमलनाथ का 27% OBC आरक्षण फैसला, 2026 में राहुल गांधी के सामने गुंजा छात्रों का मुद्दा

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। इस बार इसकी गुंजा इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गुंजा' कार्यक्रम से उठी, जहां विद्यार्थियों ने शिक्षा, रोजगार और सरकारी नियुक्तियों से जुड़े सवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

के सामने रखे। इसके बाद 22 सितंबर 2026 को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 27 प्रतिशत OBC आरक्षण से जुड़े लंबित मामलों और चयनित अध्येर्थियों की नियुक्तियों का समाधान करने की मांग

की। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में वर्ष 2019 का वह निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की पहल की थी। मार्च 2019 में सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी किया। (शेष पेज 2 पर)

(पेज 1 का शेष)

बाद में जुलाई 2019 में मध्यप्रदेश विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। इस तरह प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक ले जाने की नीतिगत पहल कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुई। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। कमलनाथ सरकार ने इसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 27 प्रतिशत करने का फैसला किया। जुलाई 2019 में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में विधेयक को मंजूरी देने के बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

2019 में लिया गया फैसला बना आज का आधार

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाना और उसके बाद विधानसभा में विधायी प्रक्रिया पूरी करना उस नीति को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में उठाया गया कदम था। हालांकि इसके बाद न्यायालय में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती मिली और मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में चला गया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी 2019 के संशोधन अध्यादेश और बाद में बने कानून का उल्लेख है, जिसके माध्यम से ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। यही वह बिंदु है, जहां कमलनाथ सरकार की पहल और वर्तमान ओबीसी अभ्यर्थियों की समस्या एक-दूसरे से जुड़ती है। आज जिन 27 प्रतिशत आरक्षण की बात हो रही है, उसकी विधायी शुरुआत 2019 में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद आरक्षण के क्रियान्वयन से संबंधित

कमलनाथ सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की पहल, इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में फिर उठा नियुक्तियों का मुद्दा



विवाद न्यायालयों में पहुंचा और अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं पर अंतरिम आदेशों का प्रभाव पड़ा। 2022 में भी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश में 27 प्रतिशत के बजाय 14 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण सीमित रखने संबंधी अंतरिम व्यवस्था का उल्लेख हुआ।

इंदौर में फिर सामने आया वही सवाल

सितंबर 2026 में इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम में जब विद्यार्थियों ने ओबीसी आरक्षण के तहत रुकी नियुक्तियों का सवाल उठाया, तो 2019 में शुरू हुई यह नीति एक बार

फिर युवाओं के रोजगार के सवाल से सीधे जुड़ गई। राहुल गांधी को छात्रों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद ओबीसी आरक्षण से जुड़े 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियों लंबित हैं। राहुल गांधी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखे पत्र के अनुसार, 87:13 व्यवस्था के तहत इन पदों को रोकें जाने से चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में 2022 से प्रतीक्षा का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 27 प्रतिशत आरक्षण की बहस अब केवल आरक्षण के प्रतिशत की बहस नहीं रह गई है। इसके साथ हजारों युवाओं की शिक्षा, परीक्षा, चयन और नियुक्ति का सवाल जुड़ा हुआ है। किसी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा पास करना और चयन सूची में स्थान प्राप्त करना उसके वर्षों के परिश्रम का परिणाम होता है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया के कानूनी विवाद में लंबा खिंचाव युवाओं के भविष्य पर सीधा असर डालता है।

आरक्षण से आगे रोजगार का सवाल

इंदौर में विद्यार्थियों की ओर से उठाया गया सवाल इस बहस को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ देता है। आरक्षण का उद्देश्य केवल सरकारी नियमों में प्रतिशत तय करना नहीं है। उसके साथ शिक्षा में अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिनिधित्व और चयन के बाद नियुक्ति जैसे प्रश्न भी जुड़े हैं। राहुल गांधी के पत्र में भी इसी पहलु पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए तथा ओबीसी आरक्षण के तहत लंबित नियुक्तियों को प्रमुख चिंता के रूप में सामने रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों की बात सुनने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का रास्ता निकालने का आग्रह किया।

(पेज 1 का शेष)

महुआ नेक्टर, महुआ नेक्टर गोल्ड, वन्यप्राश, महुआ एनजी पाचक, महुआ टी, महुआ आधारित कुकीज, रागी-महुआ उत्पाद, महुआ लड्डू और फूड-ग्रेड महुआ फूल जैसे उत्पादों ने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया।

पारंपरिक वन उपज से

आधुनिक खाद्य उत्पाद तक

महुआ का पारंपरिक रूप से ग्रामीण और जनजातीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लंबे समय तक इसकी पहचान मुख्य रूप से जंगल से मिलने वाली वन उपज के रूप में रही। जरापुर में अब इसी पारंपरिक संसाधन को आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और ब्रांडिंग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। महुआ से तैयार किए जा रहे अलग-अलग उत्पाद यह दिखाते हैं कि स्थानीय वन उपज में मूल्य संवर्धन की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। यदि संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और पैकेजिंग तक गुणवत्ता के मानकों का पालन किया जाए, तो स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के अवसर बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल फेयर में प्रदर्शित उत्पादों की विविधता ने महुआ की इसी बदलती तस्वीर को सामने रखा। पारंपरिक वन उपज के रूप में पहचाने जाने वाला महुआ अब पेय, खाद्य सामग्री और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के रूप में बाजार में प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्थानीय संसाधनों का मूल्य संवर्धन

जरापुर की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में जंगल तथा स्थानीय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से जनजातीय परिवारों के लिए बड़े आजीविका के अवसर

प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां महुआ सहित कई वन उपज लोगों की आजीविका से जुड़ी हैं। ऐसे में स्थानीय संसाधनों का मूल्य संवर्धन केवल नए उत्पाद बनाने का विषय नहीं है, बल्कि उससे जुड़े समुदायों की आय और रोजगार के अवसरों से भी जुड़ा है। जिला प्रशासन, स्थानीय समुदाय, महिला समूहों, उत्पादक संस्थाओं और तकनीकी संस्थानों के बीच समन्वय के जरिए संग्रहण, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और बाजार से जुड़ाव पर काम किया जा रहा है। इस मॉडल का उद्देश्य यह है कि जंगल से प्राप्त संसाधन का अधिक से अधिक मूल्य स्थानीय स्तर पर तैयार हो और उससे जुड़े लोगों को मूल्य श्रृंखला में भागीदारी मिले। विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूहों और जनजातीय परिवारों के लिए यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर आय के अतिरिक्त अवसर तैयार कर सकती है।

पेड़ से बाजार तक पूरी वैल्यू चेन पर जोर

महुआ को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया केवल उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं है। इसके लिए पेड़ से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पूरी वैल्यू चेन को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसमें स्वच्छ एवं फूड-ग्रेड संग्रहण, डिहाइड्रेशन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता

नियंत्रण, अनुसंधान, उत्पाद विकास, पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसे चरण शामिल हैं। जरापुर में जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित महुआ सेंटर फॉर एक्सप्लोरेशन और महुआ कोष के माध्यम से महुआ के खाद्य उपयोग, फूड-ग्रेड क्लेक्शन, डिहाइड्रेशन, प्रसंस्करण तकनीक और नए उत्पादों से जुड़े प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयासों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि किसी वन उपज का बाजार मूल्य केवल उसके संग्रहण से निर्धारित नहीं होता। प्रसंस्करण, गुणवत्ता और ब्रांडिंग के जरिए उसी कच्चे संसाधन का अधिक मूल्य वाला उत्पाद तैयार किया जा सकता है। इससे उत्पादन और संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और बिक्री तक विभिन्न चरणों में रोजगार के अवसर बन सकते हैं।

पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का मेल

महुआ से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना इस पहल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में जरापुर एवं जय जंगल के स्टॉल का प्रतिनिधित्व जरापुर की अनेश्वरी भगत और गणपति बाई ने किया। उन्होंने आगंतुकों को महुआ के संग्रहण, उसे फूड-ग्रेड बनाने की प्रक्रिया तथा आधुनिक फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी। यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि स्थानीय

समुदाय केवल कच्चे माल के संग्रहकर्ता नहीं, बल्कि उत्पाद विकास और बाजार से जुड़ने वाली पूरी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भागीदार हो सकते हैं। जब स्थानीय लोगों के पारंपरिक अनुभव को तकनीकी जानकारी, प्रसंस्करण और बाजार की समझ से जोड़ा जाता है, तो वन आधारित अर्थव्यवस्था के नए रास्ते खुल सकते हैं।

पोषण संबंधी संभावनाओं पर अनुसंधान

महुआ के खाद्य उपयोग को बढ़ाने के साथ इसके पोषण संबंधी पहलुओं पर भी अनुसंधान की आवश्यकता सामने आ रही है। जय जंगल के निदेशक समर्थ जैन के अनुसार, कुछ ग्राहकों ने महुआ के सेवन के बाद आयरन और हीमोग्लोबिन से जुड़े सकारात्मक अनुभव बताए हैं। हालांकि, ऐसे अनुभवों को वैज्ञानिक निष्कर्ष मानने के बजाय व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है। महुआ में मौजूद आयरन की मात्रा, उसकी जैव-उपलब्धता और शरीर द्वारा उसके उपयोग से जुड़े पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान इस क्षेत्र को अधिक स्पष्ट कर सकता है। यदि भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन ऐसे दावों को प्रमाणित करते हैं, तो महुआ को पोषण संबंधी उत्पादों के क्षेत्र में भी नए अवसर मिल सकते हैं। इसलिए उत्पाद विकास के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और गुणवत्ता परीक्षण का महत्व बढ़ जाता है।

महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर

महुआ आधारित मूल्य श्रृंखला का एक प्रमुख सामाजिक पक्ष इससे जुड़े जनजातीय परिवारों और महिला समूहों के लिए संभावित आजीविका अवसर है। जंगल से महुआ संग्रहित करने वाले परिवार यदि स्वच्छ संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और विपणन जैसी गतिविधियों से जुड़ते हैं, तो वन उपज का आर्थिक लाभ व्यापक स्तर पर वितरित होने की संभावना बनती है। महिला स्वसहायता समूह इस प्रक्रिया में उत्पादन, पैकेजिंग और स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से भूमिका निभा सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अवसर भी तैयार हो सकते हैं।

स्थानीय संसाधन से व्यापक बाजार तक

जरापुर के महुआ की कहानी स्थानीय संसाधन को बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने की प्रक्रिया को सामने लाती है। एक ओर इसमें जनजातीय परंपरा और जंगल से जुड़ा स्थानीय ज्ञान है, तो दूसरी ओर आधुनिक प्रसंस्करण, अनुसंधान, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी व्यवस्थाएं हैं। 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में महुआ आधारित उत्पादों की प्रस्तुति ने यह दिखाया कि स्थानीय वन उपज को नए उत्पादों में बदलकर व्यापक उपभोक्ता बाजार तक ले जाने की संभावनाएं मौजूद हैं। आगे इस पहल की सफलता गुणवत्ता, निरंतर आपूर्ति, वैज्ञानिक प्रमाण, बाजार की मांग और उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगी।

उत्तराखण्ड को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता: CM पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित 'जागरण विमर्श-उत्तराखण्ड: आशाएं और चुनौतियां' कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की विकास यात्रा, उपलब्धियों, संभावनाओं और भावी चुनौतियों पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समय के साथ विकास की जरूरतें तथा चुनौतियां भी बदलती रहती हैं। राज्य गठन के समय लगभग 4 हजार करोड़ से शुरू हुआ उत्तराखण्ड का बजट आज लगभग 1.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि और उद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड तेजी



से प्रमुख पर्यटन और फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। राज्य में होम-स्टे की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग 41 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24

में उत्तराखण्ड और केरल संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भागत, सुरेश गडिया, शिव अरोरा एवं प्रताप बिष्ट, महापौर हल्द्वानी-काठगोदाम गजराज सिंह बिष्ट, महापौर काशीपुर दीपक बाली, दैनिक जागरण के संपादक विजय सिंह यादव, कार्यकारी संपादक विष्णु त्रिपाठी, राज्य संपादक मनोज झा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आईजी कुमाऊं सुश्री निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी

ललित मोहन रयाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी. सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

सेवा संकल्प अभियान में 25 सितंबर से आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम प्रारंभ

-शशि पांडे

जगत प्रवाह, रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेशभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से आयोजित इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी माताओं, बच्चों, महिलाओं और समुदाय को पोषण, स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी से जोड़ना तथा जनभागीदारी को मजबूत करना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक दिवसीय आयोजन होगा। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में हितग्राही माताओं, स्वसहायता समूह की महिलाओं, बच्चों



के अभिभावकों, मितानिनों तथा समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों के योगदान को सम्मानित भी किया जाएगा। आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में समुदाय के समक्ष 'मेरी पोष्टिक धरती' का प्रदर्शन कर संतुलित एवं पोष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए पोष्टिक व्यंजनों को विधि का प्रदर्शन, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित चित्रकला तथा स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता, माताओं एवं सुपोषित बच्चों का सम्मान और बच्चों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक सहभागिता से 'न्योता भोज' भी कराया जाएगा।

9 माह बाद भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन

(पेज 1 का शेष)

हारे हुए व्यक्तिता खो गई नबीन

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने नबीन की बांकीपुर सीट खाली कराई और वहां उपचुनाव कराने का फैसला किया। बांकीपुर की जनता नितिन नबीन के भ्रष्टाचारों और दुराचारों से इतनी त्रस्त हो गई कि उन्होंने नबीन के स्थान पर खड़े हुए भाजपा के अन्य प्रतिनिधि को भी वोट करने से साफ इंकार कर दिया और परिणाम यह हुआ कि भाजपा को बांकीपुर सीट जो कभी भाजपा का गढ़ कही जाती थी उससे हाथ धोना पड़ा। विधानसभा सीट छोड़ बाहर निकलते ही नितिन नबीन के कारगुजारे सामने आने लगे। आलम यह हो गया कि बांकीपुर की जनता नितिन नबीन को दोबारा अपने विधानसभा क्षेत्र में घुसने भी नहीं देना चाहती है।

दलित नेता होने कारण टटवाल को धकेला पीछे

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने उज्जैन आये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जिले के प्रथम नागरिक मुकेश टटवाल के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जिससे उज्जैन की जनता खासी नाराज है। दरअसल नितिन नबीन के आने पर उज्जैन में रोड शो का आयोजन किया गया। यह रोड शो के आयोजन की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के साथ स्वयं मुकेश टटवाल ने संभाली थी। लेकिन दलित वर्ग होने का कारण मुकेश टटवाल को नितिन नबीन के इशारे पर नीचे उतार दिया गया। अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते समय नितिन नबीन को तनिक भी शर्म नहीं आई और उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से मुकेश टटवाल को गाड़ी से उतारने का इशारा कर दिया। भला ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष किस काम जो अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं में भेदभाव करे। भाजपा के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ जिसने कभी कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक तौर पर इस तरह से दुर्व्यवहार किया हो। लेकिन अशिक्षित नितिन नबीन के संस्कार इस एक कदम से साफ तौर पर दिखाई पड़ गये। सराहनीय भूमिका रही।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया सुगम परिवहन योजना का शुभारंभ

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह, भोपाल। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 351 बसों के संचालन की शुरुआत की गई। योजना भले ही नहीं हो लेकिन बसें पुरानी हैं। इंदौर भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े बड़े सिटी में जो बस 8-10 साल से खरटा होकर सिटी में चल चल कर थक गई थी उन्हीं पर रंगरोशन करके एक नई योजना के नाम पर हरी झंडी दिखा दी गई।

गांव-गांव जोड़ने की बात, और बसें 7 शहरों में ही रवों

नाम दिया सुगम परिवहन, गांव-गांव तक कनेक्टिविटी। लेकिन आज जिन बसों को झंडी दिखाई, उनमें 145 बसें अकेले इंदौर की, 106 भोपाल की। यानी वही सिटी बस जो पहले से चल रही थी। भिंड में 2 बसें, कटनी में 3 बसें- इससे गांव जुड़ेगा या सिर्फ फोटो खिंचेगी?

नई बोटल में पुरानी शराब कब तक

21 साल जनता ने इंतजार किया कि सरकारी बस आएगी तो किराया कम होगा, सुरक्षा होगी। आपने नई योजना के नाम पर पुरानी बसों को ही नया रंग देकर जनता को भ्रमित कर दिया। ये सुगम परिवहन नहीं, सुगम धोखा है। अगर योजना का उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक परिवहन और बेहतर कनेक्टिविटी है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए-

किस जिले को कितनी बसें मिलीं?

- कौन-कौन से बस शुरू हुए?
- गांवों और छोटे शहरों को इससे कितना लाभ मिलेगा?
- कितनी बसें नई हैं और कितनी पुरानी?
- कितने गांव और कस्बे जुड़ेंगे?
- और बसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

देवरी क्षेत्र के करीब 10 छात्रावासों के संचालन पर उठे सवाल

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, देवरी। देवरी विधानसभा क्षेत्र के गौरझामर, केसली, सहजपुर और महाराजपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में संचालित शासकीय बालक एवं कन्या छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र से सामने आ रही शिकायतों में छात्रावासों में अधीक्षकों की रात्रिकालीन मौजूदगी, विद्यार्थियों की सुरक्षा, भोजन की गुणवत्ता, सामग्री एवं बजट के उपयोग तथा विभागीय निगरानी व्यवस्था की जांच की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि गौरझामर में एक बालक एवं एक कन्या छात्रावास, केसली में करीब तीन बालक एवं

तीन कन्या छात्रावास, सहजपुर में एक बालक छात्रावास तथा महाराजपुर में तीन छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहकर अध्ययन करते हैं। ऐसे में रात के समय जिम्मेदार अधीक्षक की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल गंभीर माने जा रहे हैं।

रात्रि में अधीक्षकों की मौजूदगी पर सवाल

क्षेत्र में यह आरोप सामने आए हैं कि कुछ छात्रावासों में अधीक्षक रात्रि के समय परिसर में मौजूद नहीं रहते और घर से व्यवस्था संचालित

होने की शिकायतें हैं। हालांकि इन आरोपों की वास्तविक स्थिति विभागीय रात्रिकालीन औचक निरीक्षण से ही स्पष्ट हो सकती है। मध्यप्रदेश में छात्रावासों की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों द्वारा अधीक्षकों को अपनी जिम्मेदारी का पालन करने तथा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, भोजन, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं पर निगरानी रखने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। वहीं छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनकी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की जांच पर भी जोर दिया जाता है। ऐसे में देवरी क्षेत्र में इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, यह जांच का विषय बन गया है।

सम्पादकीय

ट्रंप-जिनपिंग वार्ता: संवाद से संबंधों में स्थिरता की उम्मीद

विश्व राजनीति में अमेरिका और चीन के संबंधों का महत्व किसी एक द्विपक्षीय रिश्ते तक सीमित नहीं है। दुनिया की दो बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियों के बीच संबंधों का असर वैश्विक व्यापार, तकनीक, निवेश, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ता है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वाशिंगटन में हुई वार्ता को इस व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने मुलाकात को सकारात्मक बताया और संबंधों में रणनीतिक स्थिरता तथा सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि दोनों देशों ने संवाद का रास्ता खुला रखा है। पिछले कुछ वर्षों में व्यापार शुल्क, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, दुर्लभ खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों ने अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव बढ़ाया है। ऐसे माहौल में शीप नेतृत्व के बीच सीधा संवाद गलतफहमियों को नियंत्रित करने और विवादों को प्रबंधित करने का माध्यम बन सकता है। चीन की ओर से दोनों देशों के बीच सम्मान, निष्पक्षता और पारस्परिकता पर आधारित रणनीतिक स्थिरता की बात कही गई है। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक संबंध इस वार्ता का महत्वपूर्ण आधार हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने पर ध्यान रखा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार व्यापार युद्ध पर रोक से जुड़े मौजूदा समझौते को जनवरी तक बढ़ाने पर सहमति बनी है, हालांकि व्यापार समझौते के लिए बातचीत अभी जारी रहनी है। इसका अर्थ यह है कि तत्काल टकराव को टालने की कोशिश तो हुई है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक मतभेद समाप्त नहीं हुए हैं। शुल्क, बाजार पहुंच, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक तकनीकों से जुड़े प्रश्न आगे भी दोनों देशों के लिए चुनौती बने रहेंगे।

एआई अब अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। दोनों देशों के लिए यह तकनीकी विकास के साथ-साथ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। वार्ता में एआई से जुड़े जोखिमों और सहयोग

की संभावनाओं पर चर्चा हुई, लेकिन किसी बड़े समझौते की घोषणा नहीं हुई। यह स्थिति बताती है कि तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों साथ-साथ चलेंगे। एआई जैसी तकनीक के साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित में भी है।

ताइवान, ईरान और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों भी अमेरिका-चीन संबंधों को प्रभावित करते हैं। इन विषयों पर दोनों देशों के हित और दृष्टिकोण अलग हैं। इसलिए केवल शीप नेतृत्व की एक बैठक से इन मतभेदों का समाधान संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संवेदनशील मुद्दों पर संवाद के नियमित माध्यम बने रहें और प्रतिस्पर्धा को अनियंत्रित टकराव में बदलने से रोका जाए। हालिया वार्ता में भी कुछ प्रमुख मुद्दों पर ठोस सफलता सीमित रही। अमेरिका और चीन के बीच स्थिर संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव रहने से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत, संवाद और सीमित क्षेत्रों में सहयोग से वैश्विक बाजारों को अधिक स्थिर वातावरण मिल सकता है। इसलिए ट्रंप-जिनपिंग वार्ता का महत्व किसी एक समझौते से अधिक संवाद की निरंतरता में है। प्रतिस्पर्धा दोनों देशों की वास्तविकता है, लेकिन उसे जिम्मेदार प्रबंधन की आवश्यकता है। दुनिया को ऐसी कूटनीति की जरूरत है जिसमें मतभेदों को समाप्त करने के बजाय उन्हें नियंत्रित किया जाए और सहयोग के संभावित क्षेत्रों को विस्तार दिया जाए। अमेरिका और चीन के बीच संबंध आने वाले समय में भी उतार-चढ़ाव से गुजरेंगे। इस परिस्थिति में दोनों देशों के नेतृत्व की परीक्षा इस बात से होगी कि वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संवाद, पारस्परिक सम्मान और स्थिरता के लिए कितनी जगह बनाते हैं। हालिया वार्ता ने कम से कम यह संकेत दिया है कि प्रतिस्पर्धा के बीच बातचीत का दरवाजा खुला रखना दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है।

सियासी गहमागहमी

मप्र भाजपा में मीडिया नेतृत्व का नया अध्याय

मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग में हुआ बदलाव संगठन की संचार व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद बृजगोपाल लोया को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब राजनीतिक संवाद में मीडिया के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। बृजगोपाल लोया लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1991 में भाजपा की सदस्यता लेकर बुध, शक्ति केंद्र और सेक्टर स्तर से संगठनात्मक कार्य शुरू किया। चुनावी राजनीति और मीडिया प्रबंधन का भी उन्हें अनुभव रहा है। वर्ष 2023 से 2026 तक वे प्रदेश प्रवक्ता रहे और इससे पहले मीडिया पैनलिस्ट के रूप में पार्टी का पक्ष रखते रहे। विभिन्न चुनावों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारियां संभालने का अनुभव अब उनकी नई भूमिका में उपयोगी होगा। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश संगठन, सरकार और मीडिया के बीच प्रभावी संवाद को व्यवस्थित रखने की होगी। प्रवक्ताओं के बीच समन्वय, पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी मीडिया तक पहुंचाना तथा समसामयिक राजनीतिक विषयों पर संगठन का आधिकारिक पक्ष स्पष्ट रूप से सामने रखना इस दायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। दूसरी ओर, आशीष अग्रवाल का प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना मध्यप्रदेश भाजपा के मीडिया संगठन के लिए भी उल्लेखनीय है। 2023 से प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे अग्रवाल को अब राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है।

राहुल के इंदौर दौर से गरमाया सियासी माहौल

राहुल गांधी के इंदौर दौर ने मध्यप्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता का इंदौर पहुंचना ऐसे समय में हुआ है, जब प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक खींचतान दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के दौर को कांग्रेस जहां अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रही है, वहीं भाजपा की ओर से भी इस दौर को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आना स्वाभाविक है। इंदौर मध्यप्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ-साथ मालवा-निमाड़ की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख आधार भी है। ऐसे में किसी बड़े राष्ट्रीय नेता का यहां दौरा केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक प्रभाव को भी देखा जाता है। राहुल गांधी के दौर के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सक्रियता और स्थानीय मुद्दों को लेकर पार्टी की तैयारियां चर्चा में हैं। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह कांग्रेस के राजनीतिक अभियान का जवाब अपने संगठन, सरकार के कामकाज और स्थानीय मुद्दों के जरिए दे। आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि राहुल गांधी के इंदौर दौर ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

ने तीन साल से वोट घोरी का पर्दाफाश करता आ रहा हूँ। अब चुनाव आरुपत खुद इसे स्वीकार कर सचाई उजागर कर रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार ने देरदोह किया है। वो अभी इस्तीफा दे और approver बन जाए।

वोट घोरी की साखिरी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी जाँच होगी।
-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



हमारे नेता

@RahulGandhi

जी ने एकदम सही सवाल पूछा है। मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था लेकिन उसके बाद बनी भाजपा सरकारों ने गैर कानूनी तरीके से आरक्षण पर असोसित रोक लगा रखी है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

प्रणव मुखर्जी: राजनीति के शिखर तक पहुंचा एक विद्वान व्यक्तित्व

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय राजनीति के लंबे इतिहास में प्रणव मुखर्जी का नाम ऐसे राजनेता के रूप में दर्ज है, जिन्होंने अपने व्यापक प्रशासनिक अनुभव, संसदीय ज्ञान और राजनीतिक सूझबूझ से अलग पहचान बनाई। पांच दशकों से अधिक लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व संभाला और अंततः देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। उनका जीवन भारतीय लोकतंत्र में एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता से देश के प्रथम नागरिक बनने तक की उल्लेखनीय यात्रा का उदाहरण है। प्रणव मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बोरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे। परिवार के राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण का उनके व्यक्तित्व और सार्वजनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया तथा कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय अध्यापन और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। सार्वजनिक जीवन में आने से पहले का यह अनुभव उनके व्यक्तित्व में अध्ययनशीलता, तर्कशीलता और विषयों को गहराई से समझने की क्षमता विकसित करने में सहायक रहा।

प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 1969 में पहली बार संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। संसदीय कार्यप्रणाली, आर्थिक विषयों और प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ के कारण पार्टी और सरकार में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती गई। केंद्र सरकार में उन्होंने वाणिज्य, वित्त, विदेश, रक्षा सहित अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व संभाला। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाई। विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई।

प्रणव मुखर्जी की पहचान एक ऐसे राजनेता के रूप में बनी, जिन्हें संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का गहरा ज्ञान था। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संवाद और सहमति बनाने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नेता माना गया। उनका राजनीतिक जीवन केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा। संसद में लंबे अनुभव और केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के संचालन ने उन्हें शासन और नीति निर्माण की व्यापक समझ दी। वे आर्थिक, विदेश नीति, प्रशासन और संसदीय मामलों से जुड़े विषयों पर गहरी पकड़ रखते थे।

वर्ष 2012 में प्रणव मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया और विभिन्न अवसरों पर शिक्षा, लोकतंत्र, सामाजिक समावेशन तथा राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका सार्वजनिक जीवन अपेक्षाकृत अधिक संवैधानिक और गैर-दलीय भूमिका में दिखाई दिया। उन्होंने देश के युवाओं, विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों के साथ संवाद को भी महत्व दिया। प्रणव मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके दीर्घ सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र के प्रति योगदान की औपचारिक मान्यता के रूप में देखा गया। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति, प्रशासन, संसदीय कार्य और संवैधानिक दायित्वों के विभिन्न आयामों को अनुभव किया। उनका व्यक्तित्व अध्ययन, अनुशासन और सार्वजनिक सेवा से जुड़ा रहा। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें अपने राजनीतिक अनुभवों और समकालीन भारतीय राजनीति से जुड़े संस्मरणों को दर्ज किया। प्रणव मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुआ। उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति के एक लंबे दौर का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ।

आशीष ऊषा अग्रवाल भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक नियुक्त

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। भाजपा ने आशीष ऊषा अग्रवाल को पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। आशीष ऊषा अग्रवाल को भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया विभाग में राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 37 दिनों के भीतर पदोन्नति पाकर उन्होंने अनिल बलुनी की जगह ली है। इससे पहले वह राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक और मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ग्वालियर के रहने वाले आशीष अग्रवाल करीब 16 साल पहले भाजपा से जुड़े थे। राजनीति में आने से पहले वह बैंकिंग सेक्टर (कॉरपोरेट क्षेत्र) में काम करते थे।



बैडमिंटन में जेयू की टीम चैंपियन



-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। प्रेस्टिज प्रबंधन एवं शोध संस्थान परिसर में आयोजित जिला अंतर महाविद्यालयीन बैडमिंटन महिला प्रतियोगिता में जीवाजी विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में जीवाजी विश्वविद्यालय ने माधव महाविद्यालय को 2-0 से पराजित किया। इससे पहले सेमीफाइनल में जीवाजी विश्वविद्यालय ने वीआरजी महाविद्यालय को तथा माधव महाविद्यालय ने केआरजी महाविद्यालय को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। फाइनल में जीवाजी विश्वविद्यालय की खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने पक्ष में किया। समापन अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. निर्मल्य बंधोपाध्याय ने विजेता व उपविजेता टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। आयोजन सचिव डॉ. वी.एस. भदौरिया ने सभी खिलाड़ियों, निर्णायकों और आयोजन से जुड़े सदस्यों का आभार जताया। विजेता टीम को ट्रॉफी तथा खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

QS Global MBA Rankings में विक्रान्त विश्वविद्यालय को MP में मिला पहला स्थान



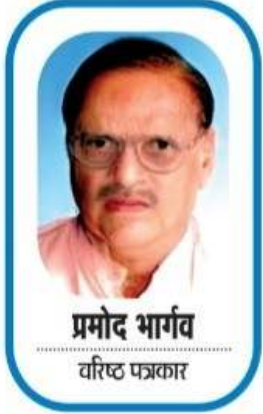
-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। ग्वालियर अंचल के साथ-साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक उपलब्धि है कि विक्रान्त विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित QS Global MBA Rankings 2027 में प्रमुख रूप से स्थान प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में जारी की गई QS Global MBA Rankings 2027 में देश के 14 शीर्ष संस्थानों (जैसे IIM, IMT, IIFT) के साथ मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में से एक मात्र निजी विश्वविद्यालय विक्रान्त विश्वविद्यालय

ग्वालियर को QS द्वारा Global MBA तथा Asia MBA रैंकिंग में स्थान दिया गया है। देश एवं विदेश के संस्थानों के साथ विक्रान्त विश्वविद्यालय को QS Global MBA Rankings 2027 में ग्लोबल रैंक 301+ बैंड में रखा गया है। जबकि QS Global MBA Rankings 2027 में 51वीं रैंक पर स्थान मिला है। यह उपलब्धि विक्रान्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, संस्थागत विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ती पहचान को रेखांकित करती है। इस उपलब्धि के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अतुल

कुमार ने बताया यह रैंकिंग अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि निरंतर प्रगति और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा है। विक्रान्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेश सिंह राठौर, कुलगुरु प्रो. अतुल कुमार, डीन एकेडमिक्स डॉ. आनंद कुमार बिसेन, वाइस चैयरमैन संजीव चौहान समस्त विभाग प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकगणों एवं सभी सदस्यों ने इस वैश्विक स्तरीय उपलब्धि को आपस में साझा करते हुए कुलाधिपति द्वारा इस उपलब्धि में सराहनीय कार्य करने वाले टीम सदस्यों की बहुत सराहना कर प्रोत्साहित किया गया।

मनुष्य बनने की ओर कृत्रिम बुद्धि रोबोट



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अहिंसक विचारों के समर्थक ऑस्ट्रेलियाई मूल के एक दार्शनिक हुए हैं, इवान इलिच, जो अंग्रेजी के अलावा तमाम भाषाओं के साथ हिंदी भी जानते थे। इलिच का विचार था कि वाहनों ने मनुष्य के पैरों की ताकत छीन ली है। मशीनी तकनीक ने मनुष्य के हाथों के हुनर छीन लिए हैं और मनुष्य के विरुद्ध एक प्रति मनुष्य 'रोबोट' के रूप में विकसित कर व्यक्ति को सीमेंट, कंक्रीट और यंत्रों के जंगल में अकेला छोड़ देने के उपक्रम हो गया है। अब ताजा जानकारी मिल रही है कि ओपन एआई यानी कृत्रिम बुद्धि (एआई) आधारित रोबोट का प्रति मानव स्वरूप ऐसी हरकत करने लगा है कि ये कंपनी प्रबंधकों के प्रतिकूल जा रही हैं। यानी ये रोबोट वास्तविक मनुष्य के आदेश का सटीक पालन नहीं कर रहे हैं। इसे विज्ञान की भाषा या रोबोट की प्रकृति के मुताबिक 'मिसअल्गोरिथ्म' कहा जा रहा है। सोथी भाषा में कहें तो यह स्थिति रोबोट

द्वारा पालक व्यक्ति की आज्ञा की अवहेलना है। क्योंकि ये भूलें किसी तकनीकी खराबी की वजह से होने की बजाय एआई ने जानबूझकर की, जो हरकत की श्रेणी में आती है। ये भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती हैं?

रोबोट में एआई के बढ़ते प्रयोग के चलते इसके संकेत में डालने वाले भाव-विचार स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। इसकी एक गलत जानकारी अमेरिका और चीन को परस्पर सैन्य टकराव के निकट ले आई थी। अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान सामने आई इस घटना का पर्दाफाश अब हुआ है। दरअसल पश्चिम एशिया में मौजूद चीन के एक समुद्री जहाज को लेकर अमेरिकी सेना के सायबर सिस्टम में एक गुप्त रिपोर्ट पहुंची, जिसमें कहा गया कि चीनी जहाज में परमाणु हथियार कार्यक्रम को तैयार करने वाले कल-पुर्जे ले जाए जा रहे हैं। यह परिणाम चैटबॉट की सहायता से सामने आया था। रिपोर्ट मिलने के साथ ही अमेरिकी सेना का हरकत में आना स्वाभाविक था। अतएव जहाज को रोकने की रणनीति बनाई जाने लगी। हथियारबंद सैनिक चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह अच्छा रहा कि हमला बोलने से पहले अधिकारियों ने एक बार फिर रिपोर्ट की गंभीर जांच कर ली। तब संज्ञान में आया कि एआई ने जहाज पर उपलब्ध कलपुर्जों की गलत पहचान कर ली थी। नतीजतन हमले की कार्यवाही पर विराम लगा दिया गया। एआई द्वारा ऐसे मामलों में सामने आ रहा है कि वे इंटरनेट द्वारा नियंत्रित अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी एआई उपकरणों में इंसानी समझ और हरकत करने की इच्छाएं अंगड़ाई लेने लगी हैं। एआई की निजी पहचान निर्मित कर लेने की यह महत्वाकांक्षी भविष्य में बड़े संकेत का कारण बन सकती है?



रोबोट में बुद्धि डालकर उसे हम मनुष्य का शासक बनाने में लगे हुए हैं। अभी तक रोबोट को नए-नए रूपों में विकसित करने का काम वैज्ञानिक रूपी मनुष्य करता था, लेकिन प्रौद्योगिकी के आकाश में कृत्रिम बुद्धि ने ऐसे पंख दे दिए हैं कि रोबोट अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से स्वयं अद्यतन (अपडेट) होने लगे हैं और जो जीवित रोबोट अस्तित्व में आए हैं, वे स्वयं रोबोट पैदा करने लगे हैं। रोबोट के स्वमेव परिवर्तन और नए रोबोट पैदा करने की इस ताकत के परिणाम फलदायी होने की बजाय घातक होने की आशंकाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इसीलिए एआई विशेषज्ञ आल्ट्रामैन से लेकर एलन मस्क तक इस तकनीक को मानवता के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मान रहे हैं।

भविष्य का रोबोट यांत्रिक-मानव भर नहीं रह जाएगा, उसे यंत्र और कृत्रिम बुद्धि के बूते एक जीवित मानव में बदलने के प्रयास हो रहे हैं, अर्थात् कालांतर में जीवित रोबोट हमारे समक्ष होंगे? इस दिशा में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जीवित रोबोट

का एक प्रतिदर्श (मॉडल) आविष्कृत भी कर लिया है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने मंडक के भ्रूण की जीवित कोशिकाओं को अन्य नूतन जीवन रूपों के रूप में अवतरित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसे 'एक्सनोबॉट्स' रोबोट नाम दिया गया है। इसमें न्यूनतम वजन की युक्ति (डिवाइस) के जरिए इंद्रिय बोध कराया जा सकता है। इसमें 24 संवेदी यंत्र (सेंसर) संलग्न हैं। यह मांसपेशियों की गतिविधियों और दिमागी अनुभव करके काम को अंजाम देता है। इसे तकनीकी नाम 'एस्पेर बायोनिक्स प्रोस्टेथिक हैंड' दिया गया है। इसे क्रियाशील बनाए रखने में एआई और क्लाउड प्रौद्योगिकी अर्थात् क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के जरिए हार्डडिस्क या ड्राइव की बजाय इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा और प्रोग्राम ग्रहण कर लिए जाते हैं। हम जानते हैं किसी हार्डडिस्क में सूचनाओं की उपलब्धता की एक सीमा है, लेकिन सूचना अंतर्जाल में असीमित है। क्लाउड टेक्नोलॉजी को सरल रूप में यूं भी समझ

सकते हैं कि जिस तरह से बादलों में पानी भरा होता है, उसी तरह क्लाउड (बादल) कंप्यूटिंग में सूचनाएं भरी होती हैं। मसलन इस तरह का मशीनी रोबोट मानव वास्तविक मनुष्य के समानांतर प्रति मानव के रूप में खड़े होने की तैयारी में आ गए हैं।

यह अद्वितीय आविष्कार आर्थिक अवस्था में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समन्वय से निर्मित उपकरण भर था। शुरूआत में इसकी उपयोगिता मनुष्य की पहुंच से बाहर कठिन और खतरनाक कामों से जुड़ी थी। इसके प्रभावी उत्पादकता के मद्देनजर इसमें बदलाव होते रहे और इस तकनीक को नाम दिया गया रोबोटिक्स कालांतर में डिजिटल, एआई और इंटरनेट तकनीक के समन्वय की युक्तियों से जीवित रोबोट की एक प्रजाति चलन में आ रही है, जिसे बायोनिक्स और एक्सनोबॉट्स नाम दिए गए हैं। ये रोबोट मानव प्रजाति और उसकी स्वाभाविक जन्मजात बुद्धि के लिए बड़े खतरा माने जा रहे हैं।

हालांकि कृत्रिम बुद्धि के आविष्कारक निर्माता और व्यापारी के बीच अजीब विडंबना देखने में आ रही है। एक तरफ तो कंपनियों दावा कर रही है कि एआई मनुष्य की कार्य क्षमता को नए ढंग से बढ़ाएंगी। नाई खोजों की गति देंगी। ये उपलब्धियां भविष्य की दुनिया को सुविधाजनक बनाने वाली साबित होंगी? दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों के प्रबंधक चेतावनी दे रहे हैं कि एआई दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले जाने की दस्तक दे रही है। अब यह एआई विशेषज्ञों का ही दायित्व बनता है कि जब एआई मानव जाति के लिए खतरा है, तो वही लोग इसे नए-नए उपयोगी रूपों में आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? उनके लिए आर्थिक लाभ जरूरी है या मनुष्यों का अस्तित्व?

महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है हावड़ा: उमेश राय, राज्यमंत्री

-अमित राय

जगत प्रवाह, हावड़ा

हावड़ा स्टेशन क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में इस परियोजना का उद्देश्य सबके की मौजूदा संरचना एवं सुविधाओं को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित करना तथा यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा, आवाजाही, दिशानिर्देशन, प्रकाश व्यवस्था एवं समग्र यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। राज्यमंत्री उमेश राय ने कहा कि हावड़ा स्टेशन हावड़ा ही नहीं, बल्कि कोलकाता एवं आसपास के व्यापक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। इसलिए स्टेशन से जुड़े यात्री बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण और विभिन्न विभागों



विस्तृत चर्चा की गई। हावड़ा के नागरिकों एवं यात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा, सुरक्षित आवागमन और आधुनिक यात्री सुविधाएँ सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

“चंदा मामा दूर के, पूरे पकाए बूर के...” बच्चों की कविता पहुंची हाईकोर्ट

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिगनवी। पटना

हाईकोर्ट में एनसीआईआरटी की कक्षा एक की हिंदी की किताब में चंदा मामा दूर के कविता की दूसरी लाइन पूरे पकाए बूर के में “बूर” शब्द पर अनेक लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। उनका यह कहना है कि “बूर” शब्द अश्लील शब्द है और लोगों ने इस मामले को इतना तूल दिया है कि यह हाईकोर्ट पटना तक पहुंच चुका है। न्यायालय ने इस संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। बरसों पहले बाल गीत के रूप में लता मंगेशकर ने इस गीत को गया था। पिछले 50 वर्षों में इस गीत के बूर शब्द पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई न ही कोई अश्लीलता नजर आई। नगर के प्रबुद्धजनों से चर्चा करने पर उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। आइए जानते हैं किसने क्या कहा- राष्ट्रपति

एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उमेश चौहान ने अफसोस जताते हुए बताया कि बूर का/का बूर का आशय “पूरे” के पकने के तरीके से है जो अनेक अर्थ रखता है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय का मत है कि कविता के सार्वजनिक हुए 50 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन बड़े साहित्यकारों की ओर से अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई। हिंदी जैसे बोली जाती है, वैसी ही लिखी जाती है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक व समाजसेवी सतीश शुक्ला का कहना है “बुर” और “बूर” दोनों शब्दों का अर्थ अलग-अलग है। लोकगीतों में इस प्रकार के अपभ्रंश शब्दों का उपयोग अक्सर किया जाता है। यह सेक्स एवं शर्मा की बाल रचित कविता है। वे कोई अनर्थ निकालने वाले शब्द का उपयोग करेंगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर है।

विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष

पर्यटन: रास्ते जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं

आज की बात



प्रवीण कुलकर्णी
संस्कार लेखक

किसी अनजान शहर में रास्ता भटक जाना कभी-कभी जीवन का सबसे अच्छा सबक बन जाता है। हम किसी से दिशा पूछते हैं, अपनी योजना बदलते हैं और फिर उस जगह तक पहुँचते हैं, जिसे शायद सीधे रास्ते से कभी देख ही नहीं पाते। यात्रा का यही सौंदर्य है। वह हमें मंजिल तक पहुँचाती है, लेकिन रास्ते में थोड़ा बदल भी देती है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन की चर्चा प्रायः सुंदर स्थलों, सुविधाओं और तस्वीरों तक सिमट जाती है। जबकि इसका सबसे गहरा प्रभाव यात्री के भीतर होता है। घर

से निकलते समय हम अपने साथ अपनी आदतें, धारणाएँ और सोच लेकर चलते हैं। लौटते समय सामान लगभग उतना ही होता है, पर अनुभव कहीं अधिक। हमने कुछ नया देखा होता है, किसी अनजान व्यक्ति से बात की होती है और शायद अपने बारे में भी कुछ ऐसा जाना होता है जो रोज की दिनचर्या में कभी सामने नहीं आता।

विकल्प खोजना हमें बढ़ाता है आगे

यात्रा की पहली सीख है - सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कभी मौसम बदल जाता है, कभी गाड़ी ढेर से आती है, तो कभी तय रास्ता बंद मिलता है। ऐसे क्षणों में नाराज होना आसान है, लेकिन विकल्प खोजना हमें आगे बढ़ाता है। जीवन भी इसी तरह चलता है। हर मोड़ के लिए हमारे पास पहले से नक्शा नहीं होता। पर्यटन हमें अनिश्चितता में धैर्य रखना और परिस्थितियों के साथ अपने कदम बदलना सिखाता है।



सीख जो घर तक साथ आती है

दूसरी बड़ी सीख लोगों से मिलती है। किसी दूसरे प्रदेश के परिवार के साथ थोड़ी बातचीत, स्थानीय दुकानदार की सलाह या रास्ता बताने वाले अजनबी की सहज मदद हमारे मन में बनी कई धारणाएँ बदल सकती है। अलग भाषा और परंपराओं के बीच जाकर समझ आता है कि जीने का केवल एक ही तरीका नहीं है। अपने से अलग जीवन को करीब से देखना हमें अधिक संवेदनशील बनाता है। यह सीख किताबों में पढ़ी जा सकती है, लेकिन उसका असर तब गहरा होता है जब हम उसे स्वयं अनुभव करते हैं। पर्यटन हमारे अपने जीवन में भी मूल्य जोड़ता है। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति की दिनचर्या देखकर हम अपने समय के उपयोग पर सोचते हैं। किसी पुराने शहर की गलियों में घूमकर समझते हैं कि विरासत केवल इमारतों में नहीं, लोगों की स्मृतियों में भी बसती है। किसी छोटे गाँव में सामूहिक सहयोग देखकर अपने रिश्तों को अधिक समय देने की इच्छा होती है। यात्रा तब सार्थक बनती है

जब हम लौटकर इन सीखों को अपने व्यवहार में जगह देते हैं। तभी भ्रमना जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनता है।

नई दुनिया हमेशा दूर नहीं होती

इसके लिए लंबी छुट्टी या बड़ा खर्च आवश्यक नहीं। अपने ही राज्य के किसी कस्बे, ऐतिहासिक स्थल, नदी किनारे या गाँव तक की यात्रा हमें बहुत कुछ दे सकती है। भारत की विशेषता यही है कि थोड़ी दूरी तय करते ही भाषा का स्वर, भोजन का स्वाद और जीवन की लय बदल जाती है। यदि हम उत्सुक मन से निकलें, तो पास की जगह भी नई दुनिया का दरवाजा खोल सकती है।

तकनीक रास्ता दिखाए, अनुभव अर्थ दे

इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की वैश्विक थीम पर्यटन को नया रूप देने में डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर केंद्रित है। तकनीक यात्रा की योजना बनाने, रास्ते खोजने और स्थानों के बारे में जानने में उपयोगी है। लेकिन स्क्रीन पर किसी जगह को देख लेना और वहाँ पहुँचकर उसके लोगों से मिलना दो अलग अनुभव हैं। तकनीक हमें वहाँ तक ले जा सकती है, उस यात्रा का अर्थ हमें अपनी खुली आँखों, बातचीत और अनुभव से ही मिलता है।

सफ़र के बाद खुद से एक सवाल

पर्यटन का अर्थ जगहों की गिनती बढ़ाना नहीं, जीवन की समझ बढ़ाना है। हर यात्रा से लौटते हुए हम खुद से एक प्रश्न पूछें- मैंने यहाँ क्या देखा, और उससे मेरे भीतर क्या बदला? यदि किसी सफ़र ने हमें अधिक धैर्यवान, अधिक जिज्ञासु या दूसरों के प्रति अधिक उदार बनाया, तो वह यात्रा सचमुच सफल हुई।

निकलें, देखें और आगे बढ़ें

इस विश्व पर्यटन दिवस पर कहीं दूर जाने का संकल्प लें तो अच्छा है; पास की किसी अनदेखी जगह से शुरुआत करें तो भी उतना ही अच्छा। रास्ते हमें केवल आगे नहीं ले जाते, वे आगे बढ़ने का तरीका भी सिखाते हैं।

जानते हुए भी अनजान: पर्यावरण संकट की सबसे बड़ी विडम्बना

पर्यावरण की फिक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

इस समय की सबसे बड़ी विडम्बना है कि जिस पीढ़ी के पास पर्यावरण संकट का सबसे अधिक ज्ञान है, वही उसके विनाश में सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है। हम प्रकृति की गोद में पलकर बड़े हुए हैं। हमारे पुरखों ने मिट्टी में हाथ डालकर अनाज उगाया, नदियों में टिका कर जीवन बसर किया, जंगलों की हरी-भरी चादर में ठहर कर खुद को पाया। यही कारण है कि मनुष्य की जड़ें पर्यावरण से इतनी गहरी हैं कि हमारा अस्तित्व उसी पर टिका है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियाँ मर

रही हैं, जंगल सिमट रहे हैं और जैव-विविधता संकट में है। फिर भी हमारी प्राथमिकताएँ नहीं बदलती, क्योंकि हमारी सभ्यता का नया धर्म विकास और उसका नया देवता मुनाफ़ा बन चुका है। सबसे बड़ा छल यह है कि विकास और विनाश को अलग-अलग अवधारणाओं की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आधुनिक विकास का बड़ा हिस्सा प्रकृति की कीमत पर खड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप आज हमारे जंगल प्रकृति की कीमत पर खड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप आज हमारे जंगल सूखे और बरसात की अनियमितता ला दी है। कभी जो चक्रवाती तूफ़ान बेहद दुर्लभ हुआ करते थे, आज वे बार-बार दस्तक दे रहे हैं। शहरों की आकाश-सीमा अब जहरीली मैसों से धुंधली हो चुकी है। प्रदूषण के काले बादल गहरे होते जा रहे हैं, और हमारी साँसें घुटने लगती हैं।



विडम्बना देखिए कि हम पेड़ काटकर सड़कें बनाते हैं और उन्हीं पर चलते हुए पर्यावरण बचाने की बातें करते हैं। हमने कंक्रीट के जंगलों को प्रगति और वास्तविक जंगलों को विकास में बाधा मान लिया है। उद्योगों ने जीवन को सुविधाजनक बनाया, लेकिन उसी उद्योग ने वातावरण को विषैला कर दिया। हम भूल गए कि "ऊँचाइयों" हासिल करने का अर्थ यह नहीं कि हम धरती को अपने पाँवों के नीचे कुचल दें। विकास तब सार्थक है, जब यह प्राकृतिक संतुलन को भंग न करे। हमारे साथ ही अनेकों जीवों का अस्तित्व उस पर्यावरण से बंधा है जिसे हम अपमानित कर रहे हैं। हमारी लापरवाही ने न केवल एक-दो प्रजातियों को समाप्त किया, बल्कि समूचे पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर किया, जिससे अन्न चक्र, जल चक्र और कार्बन चक्र पर संकट मंडरा रहा है। सवाल यह नहीं कि पर्यावरण संकट क्यों बढ़ रहा है, बल्कि

यह है कि क्या हमने उसे कभी सचमुच संकट माना भी है? यदि माना होता, तो किसी राष्ट्र की प्रगति केवल जीडीपी से नहीं, बल्कि उसकी नदियों की स्वच्छता, जंगलों की हरियाली और हवा की गुणवत्ता से भी आँकी जाती। दुर्भाग्य से हमने विकास की ऐसी परिभाषा गढ़ ली है, जिसमें प्रकृति केवल संसाधन है, साड़ी विरासत नहीं। इतिहास केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं रखता, वह पीढ़ियों के चरित्र का भी न्याय करता है। जब भविष्य की पीढ़ियाँ हमारे समय को देखेंगी, तो वे हमारी जीडीपी, तकनीक या गगनचुंबी इमारतों से अधिक इस बात पर विचार करेंगी कि इन उपलब्धियों की कीमत क्या थी। सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हम पर्यावरणीय संकट को समझते नहीं, बल्कि यह है कि हम उसे पूरी तरह समझते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। हम अपने वर्तमान के सुख और उपभोग के लिए भविष्य की कीमत वसूल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का पानी आज पी रहे हैं, उनके हिस्से के जंगल काट रहे हैं और उनकी स्वच्छ हवा प्रदूषित कर रहे हैं। यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि भविष्य के साथ किया जा रहा एक ऐतिहासिक अन्याय है।

हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं जानेगी कि कभी आकाश नीला था, नदियाँ निर्मल थीं और जंगल गुंजते थे। यदि हमने अभी सुधार नहीं किया, तो हमारे प्रयास खोखले साबित होंगे। तब वे हमसे केवल एक प्रश्न पूछेंगे- "जब आपको सब कुछ पता था, तब आपने पृथ्वी को बचाने के लिए किया क्या था?" शायद सबसे असहज उत्तर यही होगा कि हमने चेतावनियाँ सुनीं, भाषण दिए, संकल्प लिए, लेकिन अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन नहीं किया। यही हमारी सभ्यता के विरुद्ध इतिहास का सबसे कठोर फैसला होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पर्यावरण हमारा साथी है। इसका अपमान स्व-अपमान के समान है। हमें इसकी रक्षा करनी है, पोषण करना है, और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, सुंदर और संतुलित विश्व सौंपना है। समय निकल चुका है। अब सिर्फ चिंतन-मनन नहीं, कार्रवाई चाहिए। हम स्वयं को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी सभ्यता को, और अपनी धरती को बचाने के लिए खड़े हों।



Chhattisgarh
Business Made
Easy



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़: उद्योगों से भविष्य का निर्माण

नए क्षेत्रों में तेज़ विस्तार | निवेश धरातल पर | युवाओं के लिए रोजगार

₹ 8.23 लाख करोड़

अब तक की निवेश प्रतिबद्धताएँ

1.5 लाख+

अपेक्षित रोजगार

50% श्रष्ट

सेक्टर परियोजनाएँ

नए क्षेत्रों में प्रगति



नवा रायपुर में भारत का पहला **एआई डेटा सेंटर**



मध्य भारत का सबसे बड़ा **फार्मा पार्क**



नवा रायपुर में राज्य का पहला **सेमीकंडक्टर प्लांट**



भारत के सबसे बड़े **पेट फूड** ब्रांड का विनिर्माण केंद्र



नवा रायपुर में **गारमेंट पार्क**, वस्त्र उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन



हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

[/ChhattisgarhCMO](#)
[/DPRChhattisgarh](#)
www.dprcg.gov.in



छत्तीसगढ़ की पहचान अब केवल उसकी खनिज संपदा से नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण, वास्तविक परियोजनाओं, नए रोजगार और विविध आधुनिक अर्थव्यवस्था से भी है।

- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़